



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 527]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 13, 1986/कार्तिक 22, 1908

No. 527]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 1986/KARTIKA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1986

ग. नं. नि. 1200(घ) :- केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी और  
विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 (1985 का 31)  
को धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित  
नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम  
आतंकवाद और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1986 है।  
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जहाँ तक कि संदर्भ से अन्यथा  
अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम से आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण)  
अधिनियम, 1986 (1985 का 31) अभिप्रेत है;

(ख) "सहायक प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय  
सरकार या किसी राज्य सरकार या संविधान के अनुच्छेद  
239 के अधीन किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक है या  
केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा अधिकारी है जो उस सरकार के  
संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं है या किसी

राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का ऐसा अधिकारी जो  
जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से निम्नपंक्ति का नहीं है या कोई  
ऐसा अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का किसी  
विधि के अधीन प्रयोग करने के लिए सक्षम हो;

(ग) "आवश्यक सेवा" के अंतर्गत वे सेवाएँ होंगी जिनको केन्द्रीय  
सरकार ने आवश्यक सेवाएँ बनाए रखने को अधिनियम, 1981  
(1981 का 40) के उपबंधों के अधीन ऐसा घोषित किया है;

(घ) "आवश्यक प्रदायों" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत हैं जिनको केन्द्रीय  
सरकार, यह राय होने पर कि उसके प्रदाय को बनाए रखना  
समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा  
आवश्यक वस्तु घोषित करती है;

(ङ) "समाचार पत्रों" के अंतर्गत समाचारपत्रों और अन्य प्रताप्राप्त  
रूप से परिचालित मुद्रित सामग्री के अलावा हस्तलिखित  
इशतहार, पुस्तिकाएँ, हेंडबिल्ल या सार्वजनिक स्थानों पर नारों  
का संप्रसारण भी है;

(च) "अधिवृत्ति" और "अधिवृत्ति" से राजपत्र में अधिवृत्ति  
और अधिवृत्ति अभिप्रेत है;

- (छ) "शासकीय दस्तावेज" के अंतर्गत सरकार या संघ के सशस्त्र बलों के किसी प्राधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन जारी किया गया कोई पारपत्र, पास, अनुज्ञा पत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञापत्र, सूचना या अन्य दस्तावेज है;
- (ज) "बिहित" से इन नियमों में से किसी के अनुसरण में किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश द्वारा बिहित अभिप्रेत है;
- (झ) "प्रतिषिद्ध स्थान" से शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) को धारा 2 के खंड (8) में यथा परिभाषित कोई प्रतिषिद्ध स्थान अभिप्रेत है;
- (झा) "संरक्षित क्षेत्र" से नियम 8 के अधीन इस प्रकार घोषित कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ठ) "संरक्षित स्थान" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार घोषित कोई स्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा ग्यालान का या भवन भी है, जहां अधिनियम के अधीन मामलों के संबंध में विचारण या अन्य कार्य-वाहियों की जाती है;
- (ड) "लोकसेवक" के अंतर्गत भारतीय रेंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में यथापरिभाषित कोई लोकसेवक भी है;
- (ड) "भाषण" के अंतर्गत पहले से रिकार्ड किए हुए भाषण भी है;
- (ड) "बेतार तार यांत्रिकी साधन" का वही अर्थ है जो उसका भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) में है।
3. निर्बंधन :—(1) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन नियमों के निर्बंधन पर जैसे ही लागू होगा जैसे वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्बंधन पर लागू होता है।
- (2) इन नियमों में किसी केन्द्रीय अधिनियम के प्रति किसी निवेश का, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें वह केन्द्रीय अधिनियम प्रवृत्त नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्समान विधि के प्रति कोई निवेश भी है।
- (3) यदि इन नियमों के निर्बंधन के बारे में कोई प्रश्न पैदा होता है तो वह बिनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा।

#### 4. कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार का पूर्ण अनुमोदन आवश्यक होता

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के ऐसे उपबन्धों द्वारा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी सारीख से जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को प्रवृत्त किसी शक्ति का प्रयोग या अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का निर्वहन, यथास्थिति, किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए या उस राज्य सरकार या प्रशासक द्वारा उक्त निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

#### 5. इन नियमों या उसके अधीन बनाए गए आदेशों का अनुपालन

यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिससे इन नियमों का कोई उपबन्ध संबंधित है या जिसको इन नियमों के अनुसरण में किया गया कोई आदेश संबोधित किया गया है या उससे संबंधित है या जिसके अधिभोग, कब्जा या नियंत्रण

में ऐसी कोई जगह या स्थावर संपत्ति या कोई अन्य चीज है जिससे ऐसा उपबन्ध संबंधित है, या जिसके संबंध में ऐसा आदेश किया जाता है :—

(क) विधि पूर्ण प्राधिकार या प्रतिहेतु के बिना—

(i) ऐसे उपबन्ध के संबंध में जो स्वयं उससे संबंधित है, या

(ii) किसी जगह या स्थावर संपत्ति या अन्य चीज की बाबत जिसका अधिभोग, कब्जा या नियंत्रण उसके पास है,

ऐसे उपबन्ध या आदेश का अनुपालन करने या अनुपालन सुनिश्चित करने में असफल रहेगा; या

(ख) किसी अन्य रीति से ऐसे उपबन्ध या आदेश का अवबन्धन करेगा या अवबन्धन करने का प्रयत्न करेगा— तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे उपबन्ध या आदेश का उल्लंघन किया है और इन नियमों में "उल्लंघन" पद के अंतर्गत उसके व्याकरणिक रूपरेखा के साथ कोई प्रसक्तता अवबन्धन या अवबन्धन करने का प्रयत्न भी है।

6. प्रतिषिद्ध स्थान—(1) कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं होगा या उसमें नहीं गुजरेगा अथवा उसके आसपास नहीं घूमेगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश करने या उस पर या उसमें होने या उससे गुजरने की अनुज्ञा दे दी जाती है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते हुए अपने आचरण को विनियमित करने वाले ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किए जाएं।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश करने वाले या उसमें प्रवेश चाहने वाले या उस पर या उसमें होने या उसमें जाने या गुजरने या गुजर कर आने वाले किसी व्यक्ति और ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा लाए गए किसी यान, जलयान, वायुयान या जोर को तलाशों से सकेगा और तलाशी के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति, यान, जलयान, वायुयान या चीज को निरुद्ध कर सकेगा।

परन्तु इस उपनियम के अनुसरण में किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के उल्लंघन में किसी प्रतिषिद्ध स्थान में है तो ऐसी किमी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जाएं, प्रांतिक प्रभाव डाले बिना उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किमी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति इन नियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में किसी प्रतिषिद्ध स्थान में है तो वह कारावास के जिसकी अबधि छह मास से कम हो नहीं होगी, किन्तु जो तान सर्व तक की हो सकेगी, और जुमानि में भी, रंडनीय होगा।

7. संरक्षित स्थान :—(1) यदि किसी स्थान या स्थानों के किसी वर्ग को बाबत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनमें निवृत्ति के लिए यह आवश्यक या समीचीन समझती है कि ऐसे किसी स्थान या स्थानों पर अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को ऐसे किसी स्थान या स्थानों में या उनके आसपास पहुंचने या उपस्थित होने से अवर्तित करने के लिए विशेष पूर्वावधानियां ली जानी चाहिए, तो वह सरकार आदेश द्वारा यथास्थिति, उस स्थान या उन वर्ग के प्रत्येक स्थान को ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, संरक्षित स्थान घोषित कर सकेगी। ऐसे दिन को

और उक्त परवात जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और ऐसी छूटों के अधीन जो उसमें दी जाएं, कोई भी व्यक्ति, जो यथास्थिति, लोकसेवक या कोई स्थायीधीन या न्यायालय का कोई अधिकारी या कोई अभियुक्त नहीं है, उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए लिखित अनुज्ञापत्र के निबंधनों के अनुसार ही वहां रहेगा अन्यथा नहीं।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी किए गए आदेश की एक प्रति अंग्रेजी में और उस परिशेष की जनभाषा, में संरक्षित स्थान के किसी सहजबुद्ध भाग पर लगाई जाएगी।

(3) कोई पुलिस अधिकारी, या सशक्त प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने वाले या उसमें प्रवेश करना चाहने वाले या उस पर या उसमें होने वाले या उससे जाने वाले किसी व्यक्ति की और ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा वहां लाए गए किसी यान या सामान की तलाशी ले सकेगा और तलाशी के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति या सामान को निरुद्ध कर सकेगा :

परन्तु इस उपनियम के अनुसरण में किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ही ली जाएगी, अन्यथा नहीं।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में है या उससे गुजरता है या वह स्वयं को या उस यान या चीज को जो उस समय उसके कब्जे में है, तलाशी के लिए अर्पणित करने से इंकार करता है, तो ऐसी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जाएं, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे किसी स्थान पर सुरक्षा ड्यूटी पर मैनात किसी अन्य व्यक्ति के निवेश द्वारा या उसके अधीन वहां से हटाया जा सकेगा। तदुपरि, ऐसे यान या चीज को भी, जो इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के कब्जे में पाई जाती है, अभिगृहीत किया जा सकेगा या अभिगृहीत किए जाने का निवेश दिया जा सकेगा।

(5) इस नियम के उपबन्धों का उल्लंघन, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जूमनि से भी, बंडनीय होगा।

8. संरक्षित क्षेत्र :—(1) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए किसी क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह सरकार, किसी अन्य नियम के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा उस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकेगी और तदुपरि, या तब तक जब तक वह आदेश प्रवृत्त रहता है, ऐसा क्षेत्र इन नियमों के प्रयोजनों के लिए संरक्षित क्षेत्र होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी किए गए आदेश की प्रति अंग्रेजी में और उस परिशेष की जनभाषा में संरक्षित स्थान के किसी सहजबुद्ध भाग पर लगाई जाएगी।

(3) ऐसी तारीख को और उसके पश्चात् जो उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी किन्हीं छूटों के अधीन रहते हुए जिनके लिए उपनियम (1) में उपबंध किया जाए, कोई भी व्यक्ति जो उक्त दिन के प्रारंभ में उक्त आदेश द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए किसी क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था, उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा उसको दिए गए अनुज्ञापत्र के निबंधनों के अनुसार ही वहां रहेगा अन्यथा नहीं।

(9) कोई पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने वाले या प्रवेश करना चाहने वाले या वहां या उसमें होने वाले या उससे जाने वाले किसी व्यक्ति की और ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा लाए गए किसी यान, जलयान, वायुयान या चीज की तलाशी ले सकेगा और तलाशी के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति, यान, जलयान, वायुयान या चीज को निरुद्ध कर सकेगा :

परन्तु इस उपनियम के अनुसरण में किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ही ली जाएगी, अन्यथा नहीं।

(5) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित क्षेत्र में है या उससे गुजरता है, तो किन्हीं ऐसी अन्य कार्यवाहियों पर, जो उसके विरुद्ध की जाएं, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षित स्थान पर ड्यूटी पर मैनात संघ के सशक्त बलों के किसी सदस्य के निदेश द्वारा या उसके अधीन उसे वहां से हटाया जा सकेगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित क्षेत्र में है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जूमनि से भी, बंडनीय होगा।

9. किसी गारड पर बल प्रयोग या उसका अपवर्जन करना :—ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे अकेले या व्यक्तियों के किसी समूह के भाग के रूप में,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति पर जो ऐसे किसी स्थान का संरक्षण करने या वहां पहुंचने का निवारण या नियंत्रण करने के प्रयोजन के लिए मैनात किया गया है, किसी अपराधिक बल का प्रयोग करके या उसको घमकी देकर, या

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति से अपने प्रवेश या बर्ग प्रयत्नित प्रवेश को छिपाने के लिए पूर्वबधानियां लेने के पश्चात्—

किसी प्रतिविद्ध स्थान या किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या करने का प्रयत्न करेगा या उससे गुजरेगा या गुजरने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जूमनि से भी, बंडनीय होगा।

10. कुछ स्थानों और क्षेत्रों के लिए आदेश :—(1) किसी अन्य नियम के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी अन्य स्थान या क्षेत्र की बाबत जिसके संबंध में उसे यह प्रतीत होता है कि आतंकवादी क्रियाकलापों के निवारण के लिए और उनसे निपटने के लिए विशेष पूर्वबधानियां बनाना आवश्यक या समीचीन है, ऐसे स्थान या क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश को और उसके आसपास व्यक्तियों के आवरण को नियंत्रित या विनियमित करने के लिए आदेश कर सकेगी।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी स्थान या क्षेत्र के संबंध में उपनियम (1) के अधीन किए गए आदेशों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा—

(क) ऐसे स्थान या क्षेत्र में व्यक्तियों या किसी वर्ग के व्यक्तियों के प्रवेश को निर्बंधन करना और वहां से ऐसे किसी व्यक्ति को जो वहां है, आदेशों के उल्लंघन में हटाया या जो निम्नलिखित के लिए सिद्धबोध ठहराया गया है—

(i) इन नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन, या

(ii) लोक व्यवस्था के विरुद्ध कोई अपराध,

(ख) ऐसे किसी स्थान या क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग की उपस्थिति को सशक्त प्राधिकारी द्वारा अधिभूषित किए जाने की अपेक्षा करने के लिए और ऐसे किसी व्यक्ति से जो किसी ऐसे अपराध का जो इस उपनियम के खंड (क) में वर्णित है, सिद्धबोध ठहराया गया है, अपनी गतिविधियां ऐसे स्थान या क्षेत्र में रहने के दौरान रिपोर्ट करने की अपेक्षा करना और ऐसे प्राधिकारी द्वारा उस पर अधिरोपित ऐसी अन्य शर्तों का पालन करना,

(ग) ऐसे किसी स्थान या क्षेत्र में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किसी विहित वस्तु के कब्जे या नियंत्रण में होने से प्रतिविद्ध करना।

(3) ऐसे किसी स्थान की जाँच जो कोई प्रतिषिद्ध स्थान या संरक्षित स्थान नहीं है, इस नियम के अधीन किए गए किम्हीं आदेशों में यह निवेशित किया जा सकेगा कि इन नियमों के सभी या कोई उपबंध जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान या संरक्षित स्थान को या उसके संबंध में लागू किए जाने के लिए अविव्यक्त हैं, ऐसे स्थान को या उसके संबंध में जिसके संबंध में आदेश किया जाता है, उपान्तर्गत के बिना या ऐसे उपान्तर्गत, के अधीन रहते हुए जो आदेश में किए जाएं, लागू होंगे।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी और जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

11. कुछ परिसरों पर अतिचार—(1) कोई भी व्यक्ति सरकार के प्रयोजन के लिए या आतंकवादी या बिम्बसक क्रियाकलापों से निपटने के लिए या आतंकवादियों और बिम्बसकारियों से संरक्षण के लिए प्रयुक्त या काम में लाई गई किसी परिसर पर या उसके आसपास अपराधिक अतिचार नहीं करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (1) के उल्लंघन में किसी परिसर पर अतिचार करता पाया जाता है तो वह, ऐसी किसी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विषय को जाएं, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या सरकार की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या परिसरों का अधिभोग रखने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे परिसरों से हटाया जा सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति लोक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए या भारत को प्रभुता और राज्यसौख्य अखंडता बनाए रखने के लिए संविधान के अधीन राज्य द्वारा आबद्ध किसी लोक सेवक या किसी व्यक्ति के क्षेत्र को संकटापन्न करने के लिए ऐसे किसी परिसर में या उसके आसपास नहीं होगा, जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, और जहाँ, इस उपनियम के आधार पर ऐसे किसी व्यक्ति के विषय को गई किसी कार्यवाही में यह साबित हो जाता है कि वह तात्कालिक समय पर ऐसे परिसर में या उसके आसपास उपस्थित था, तो अधिभोग ऐसे व्यक्ति के कठिने के बारे में ऐसा साध्य (जिसके अन्तर्गत किसी अपराध के लिए उसके पहले सिद्धोप ठहराए जाने का साध्य भी है) दे सकेगा जो यह बतलाता है कि वह लोक सुरक्षा या भारत की प्रभुता और राज्यसौख्य अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान के अधीन राज्य द्वारा आबद्ध किसी लोक सेवक या किसी व्यक्ति के क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपस्थित था।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो उपनियम (3) के उल्लंघन की दशा में, सात वर्ष तक की हो सकेगी, और किसी अन्य दशा में, तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

12. कुछ परिसरों के आसपास घूमना—(1) किसी संरक्षित स्थान या किसी ऐसे प्रतिषिद्ध स्थान या किसी अन्य स्थान के आसपास, जो नियम 10 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट है, घूमने वाला कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या सरकार की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उक्त परिसरों के अधिभोग में के किसी व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसे छोड़ने के लिए आदेश दे दिए जाने के परचात् उस परिक्षेत्र में घूमना जारी नहीं रखेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

13. सड़क आदि को बन्द करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से—

- (क) किसी सड़क, पथ, नहर या जलमार्ग के प्रयोग को,
- (ख) किसी भूमि पर किसी व्यक्ति, पशु या यान के मार्ग या ऐसे किसी पशु या यान द्वारा व्यक्तियों के बहन को,
- (ग) किसी यान या यानों के किसी वर्ग द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की सड़क, पथ, नहर या जलमार्ग द्वारा यात्रा को,

आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिषिद्ध या निर्बंधित कर सकेगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

14. टेलीफोन और तार का नियंत्रण—(1) जहाँ सशक्त प्राधिकारी का विश्वास हो जाता है या उसने पास यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी अविज्ञात के किसी टेलीफोन कनेक्शन या टेलीफोन साधित्र का प्रयोग किसी आतंकवादी या बिम्बसक क्रियाकलाप प्रयोजन के लिए, या उसकी सहायता करने या उसके बुद्धरण के लिए या उसकी सहायता या बुद्धरण को कोई तैयारी करने के लिए किया जा रहा है, यहाँ वह आदेश द्वारा—

- (क) यह निदेश दे सकेगा कि प्रसंगत टेलीफोन कनेक्शन ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाए, काट दिया जाए और परिसरों में के सभी टेलीफोन साधित्र और फिटिंग का कब्जा ऐसे व्यक्ति द्वारा ले लिया जाए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए,
- (ख) लिखित रूप में आदेश द्वारा इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को टेलीफोन प्रणाली पर वार्तालाप या कोई विनिर्दिष्ट वार्तालाप सुनने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा,
- (ग) किसी क्षेत्र में तार और टेलीफोन सेवा के सरकार के प्रयोजनों से अवस्था प्रयोग को निलंबित या विनियमित करने के लिए, जो तत्समय किसी ऐसे क्षेत्र का गठन करता है या उसका भागक है जो तत्समय प्रयुक्त किसी अधिनियमित के अधीन उपबन्धस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, उपबंध कर सकेगा,
- (घ) किसी प्राइवेट टेलीफोन केन्द्र या ऐसे केन्द्र के साथ किसी कनेक्शन का निर्वन्ग या निदेश अपने हाथ में ले सकेगा या किसी व्यक्ति को उसका निर्वन्ग या निदेश ग्रहण करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगी।

15. नेट-ड्राक पत्र-व्यवहार को संयुक्त करने वाले यात्रियों आदि को प्रतिषिद्ध करने और उनकी तलाशी लेने की शक्ति—

(1) इस नियम में, "फोटो" के अन्तर्गत ऐसी फोटो-ग्राफी प्लेट, फोटोग्राफी फिल्म या अन्य सुप्राहित वस्तु है जो किसी कमरे में उद्भासित की गई है भले ही ऐसी प्लेट, फिल्म या अन्य वस्तु को विकसित किया गया हो या नहीं।



(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी कि ऐसी किन्हीं छूटों के अधीन, जिनके लिए आदेश द्वारा उपबंध किया जाए, और ऐसी शर्तों के, जो उसमें अन्तर्बिष्ट हों, अनुसार के सिवाय किसी प्रकार का कोई भी लेख जिसमें सूचना रिकार्ड की गई हो, और कोई वस्तावेज, लिखात्मक प्रस्तुतीकरण, फोटो या फायो-फोन रिकार्ड या कंसेट को आतंकवादी क्रियाकलाप या विध्वंसकारी क्रियाकलाप किए जाने का पक्ष समर्थन, दुर्धरेण सलाह या उसका उद्दीपन करता है या जानबूझकर उसका किया जाना सुकर बनाता है, डाक से अस्पष्ट, भारत में या भारत से नहीं भेजे जायेंगे या संसूचित नहीं किए जायेंगे।

(3) कोई भी व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कोई वस्तु भेजने या संसूचित करने के प्रयोजन के लिए उसे अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन किसी आदेश द्वारा भारत में या भारत से कोई वस्तु भेजने पर अधिरोपित प्रतिबंध या निरन्धन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन अधिरोपित किया गया है और पता लगाने, तलाशी और अभिग्रहण के प्रयोजन के लिए उस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे :

परन्तु सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) या उसके अधीन किए गए किन्हीं आदेशों में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के उल्लंघन की बाबत कोई परिशद ऐसे किसी अभिहित ग्यापालय द्वारा बिचारणीय होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा कोई उल्लंघन हुआ या या ऐसे अन्य अभिहित ग्यापालय की अधिकारिता के भीतर होगा जिसको मामला अधिनियम की धारा 9 को उपधारा (2) या उपधारा (3) के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरित करा दिया जाए, और अभियुक्त व्यक्ति सिद्धबोध ठहराए जाने पर, कारावास में, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो नान वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

(5) कोई सीमा-शुल्क अधिकारी, इस नियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी कार्रवाई (जिनके अन्तर्गत किसी वस्तु को किसी प्रसंस्करण के अधीन करना भी है) कर सकेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि क्या किसी वस्तु में विनिविष्ट प्रकृति को कोई सूचना अभिलिखित है अथवा नहीं।

(6) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आदेश द्वारा इस नियम के प्रयोजनों के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा या उसके अधीन सीमा-शुल्क कलक्टर या किसी अधीनस्थ सीमा-शुल्क अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगी।

16. भारत में प्रवेश करना:— (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह सुनिश्चित करने के लिए उपबन्ध बना सकेगी कि ऐसी छूटों के अधीन रहने हुए जिनका आदेश में उपबंध किया जाए, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई वर्ग, भारत के बाहर किसी स्थान से आगमन पर, भारत में ऐसे स्थान से जो आदेश में विनिविष्ट किया जाए, अव्यक्त प्रवेश नहीं करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश या पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) के अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबन्धों के उल्लंघन में भारत में प्रवेश करेगा तो वह ऐसा अन्य कार्रवाई पर जो उसके विरुद्ध की जाए, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

17. भारत में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों द्वारा सूचना का प्रभाव किया जाना :

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग से जिसने भारत में प्रवेश किया है या जिसके बारे में यह विश्वास करने का प्रथमदृष्टया आधार है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के भारत में रहने के दौरान ऐसे किसी क्रियाकलाप में संलग्न होने की संभावना है जिससे भारत में लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता विच्छिन्न हो सकती है या अन्यथा भारत में किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी क्रियाकलाप का उद्दीपन, पक्ष समर्थन, दुर्धरेण किया जा सकता है या उसकी सलाह दी जा सकती है या जानबूझकर उसे सुकर बनाया जा सकता है, तो ऐसी तारीख में जो इस प्रकार विनिविष्ट की जाए, स्वयं या अपने आश्रितों, अपने अंतोत्त की और भावी गतिविधियों तथा उसके कब्जे में के किसी याता वस्तावेज की बाबत ऐसी रीति से जो विनिविष्ट की जाए, ऐसी विनिविष्टियां, जो उस आदेश में विनिविष्ट की जाएं, समस्त प्राधिकारी को देने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

18. आतंकवादियों और विध्वंसकारियों की सहायता करने वाले व्यक्तियों के साथ सम्पर्क : (1) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के साथ सम्पर्क या उनके साथ सहयुक्त नहीं होगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि ऐसा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग आतंकवादियों और विध्वंसकारियों की सहायता करने में लगा हुआ है।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

19. आतंकवादियों और विध्वंसकारियों को सूचना या अन्य सहायता देने के लिए संभाव्य वस्तुएं : (1) इस नियम में "आतंकवादियों और विध्वंसकारियों की सहायता करने के लिए संभाव्य जानकारी" से कोई ऐसी सूचना चाहे वह सही हो या मिथ्या या किसी प्रकार का कोई वस्तावेज या कोई अन्य अभिलेख अभिग्रत है, जिसमें ऐसी कोई सूचना चाहे वह सही हो या मिथ्या अन्तर्बिष्ट या अन्तर्बिष्ट करने के लिए तात्पर्यित है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित करने के लिए प्रकल्पित है जो भारत के किसी क्षेत्र या भाग में अशान्ति या भयकारित कर सकती है या शान्तिपूर्ण अवस्थाओं के बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करने के लिए आशयित या संभाव्य है या भारत के लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य, शत्रुता या घृणा की भावना फैलाने के लिए या अन्यथा किसी आतंकवादी कार्य या विध्वंसकारी क्रिया-कलाप के किए जाने को सुकर बनाने के लिए आशयित या संभाव्य है, अर्थात् :—

(क) संघ के सशस्त्र बलों या किसी भी नाम से ज्ञात किसी राज्य के पुलिस बल की कोई संकिया या प्रसिद्ध संकिया,

(ख) भारत के या उसके किसी वर्ग के नागरिकों को बलाए या भारत की प्रभुता और राज्यसौखीय अखण्डता की दृष्टि से नागरिकों या वर्ग की सहानुभूतियां,

(ग) परिवहन, संचार, प्रतिष्ठित स्थानों, संरक्षित, स्थानों, समुदाय के लिए आवश्यक प्रशास्य और सेवाओं के संरक्षण से संबंधित कोई प्रबंध, भारत की प्रभुता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए संविधान के अधीन राज्य द्वारा आवद्ध किसी लोक सेवक या व्यक्तियों की सुरक्षा और इसके अन्तर्गत कोई

ऐसी सूचना भी है, जिससे निम्नलिखित आशयित या संभाव्य है,—

- (i) भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा फैलाना या उसका अवमान करना या अप्रीति प्रदीप्त करना,
- (ii) संघ के सशस्त्र बलों या किसी राज्य के किसी भी नाम से ज्ञात पुलिस बल या किसी लोक सेवक या लोक सेवकों के किसी वर्ग के प्रति घृणा फैलाना या उनका अवमान करना अथवा अप्रीति प्रदीप्त करना,
- (iii) भारत के व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना फैलाना या अन्यथा उनके बीच मेल मिलाप पर प्रभाव डालना,
- (iv) जनसाधारण में या जनसाधारण के किसी वर्ग में भय या आतंक पैदा करना, या
- (v) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साधारणतः लोक-सेवकों या लोक सेवकों के किसी वर्ग या किसी व्यक्ति लोक सेवक के विरुद्ध आपराधिक बल के प्रयोग के लिए उकसाना।

(2) विधिपूर्ण प्राधिकार या प्रतिष्ठे के बिना कोई भी व्यक्ति,—

- (क) किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को किसी भी प्रकार कोई ऐसी सूचना जो आतंकवादियों और विध्वंसकारियों की सहायता करने के लिए संभाव्य है, अभिप्राप्त संगृहीत, अभिलिखित, प्राप्त नहीं करेगा, उसे नहीं बनाएगा या उसका मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा या किसी भी साधन द्वारा उसे वितरित या संसूचित नहीं करेगा अथवा नहीं फैलाएगा, या
- (ख) ऐसा कोई प्रकाशन जिसमें ऐसी कोई सूचना है, नहीं करेगा, मुद्रित नहीं करेगा, उसका प्रकाशन या वितरण नहीं करेगा या उसे किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करेगा;
- (ग) किसी सूचना के लेखक, सम्पादक, मुद्रक या उसके प्रकाशक या ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा जो अन्यथा ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत करता है जो आतंकवादियों और विध्वंसकारियों की सहायता करने के लिए संभाव्य है या कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत किसी समाचार एजेंसी का कोई रिपोर्टर या संचालक भी है या पत्रकार उस प्रकृति को कोई सूचना वितरित नहीं करेगा या उसका विक्रय नहीं करेगा जिसकी प्रकृति के बारे में यह जानकारी है ;
- (घ) किसी हथकड़ी, प्रबन्धक या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं करेगा, जिसके नियंत्रण में कोई ऐसा स्थान है जिसमें किसी अभिनय, मूक अभिनय, नाटक या कविता पाठ का सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम किया जाता है, या ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उसमें भाग लेता है, जिसके फलस्वरूप आतंकवादियों और विध्वंसकारियों की सहायता करने के लिए संभाव्य कोई जानकारी प्रकाशित हो जाती है, या कोई बीडियों या कैसेट जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्निहित है, प्रकाशित किया जाता है।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

20. आतंकवादियों या विध्वंसकारियों आदि से प्राप्त सामग्री के प्रकाशन का प्रतिषेध:—(1) कोई भी व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसा कोई दस्तावेज नहीं बनाएगा, उसका मुद्रण, प्रकाशन या वितरण नहीं करेगा या किसी भी प्रकार से उसका प्रसार नहीं करेगा जिसमें ऐसी सामग्री अन्तर्निहित है जो आतंकवादियों या विध्वंसकारियों, उनसे सहानुभूति रखने वालों या सहयोगियों से या आतंकवादियों, विध्वंसकारियों द्वारा प्रायोजित या प्रयुक्त या अथवा उनसे संसक्त स्त्रोतों से या उनके सहयोगियों या सहानुभूति रखने वालों से प्राप्त की गई है।

(2) उपनियम (1) के उल्लंघन से उद्भूत होने वाली किसी कार्यवाही में जो अभिलिखित दस्तावेज की यह प्रतीति हो कि —

- (1) आतंकवादियों या विध्वंसकारियों द्वारा प्रकाशित या नियंत्रित किसी प्रकार प्रसारण केन्द्र से विषय वस्तु का सार प्रसारित किया जाता है, या
- (2) आतंकवादियों या विध्वंसकारियों द्वारा किसी भी रूप में, वितरित किसी दस्तावेज में प्रकाशित किसी सामग्री की विषय-वस्तु का सार किसी दस्तावेज या कैसेट में किसी पत्राचारकर्ता सचय में चाहे उसी रूप में या किसी निम्न रूप में चाहे टिप्पणों सहित या उन के बिना पुनः प्रस्तुत की जाती है, तो पत्राचारकर्ता द्वारा पत्राचारण कर सकेगा कि यथास्थिति, दस्तावेज-या कैसेट में अन्तर्निहित सामग्री किसी आतंकवादी या विध्वंसकारों स्त्रोत से अभिप्राप्त की गई है।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के उपबन्ध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण:—इस नियम में “दस्तावेज” के अन्तर्गत ग्रामोफोन रिकार्ड, कैसेट, टेप, साउंड ट्रैक और ऐसी अन्य वस्तुएं हैं, जिन पर आवाज, वाद सं पुनः प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्य से भरी गई है।

21. कतिपय परिस्तरों के संबंध में उपाय:—(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे परिस्तरों को बाधित, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं,—

- (क) परिस्तरों के स्वामी या अभिभोगी से ऐसे उपाय करने को अपेक्षा कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, या
- (ख) किसी व्यक्ति को ऐसे उपाय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं,

जो उस सरकार की राय में, आतंकवादियों या विध्वंसकारियों द्वारा कोई आतंकवादी कार्य या विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने या उसकी योजना बनाने या उसकी तैयारी करने के लिए परिस्तरों के प्रयोग को रोकने के लिए या आतंकवादियों या विध्वंसकारियों के विरुद्ध ऐसी संक्रियाओं के दौरान ऐसे परिस्तरों में या उनके आसपास व्यक्तियों और संपत्ति को होने वाले खतरे को कम करने के लिए आवश्यक हों।

(2) यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

22. आयुधों, बिस्फोटकों आदि का कब्जा, प्रयोग या ध्वयन: (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित के कब्जे, वाहन, प्रयोग, विक्रय या अन्य ध्वयन पर प्रतिषेध, निर्वन्धन या शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।

(क) आयुध या वस्तुएं जिन्हें आयुध के रूप में प्रयोग किया जा सकता है,

(ख) गोलाबाकूब,

(ग) खतरनाक पदार्थ,

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “खतरनाक पदार्थ” से निम्नलिखित अभिप्रेत है:

(1) ऐसे पदार्थ जो बिस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अधिनियमित बिस्फोटक घोषित किए गए हैं, और

(2) ऐसे पदार्थ जो (ऐसे पदार्थ हैं जिनका बिस्फोटकों के विनिर्माण में प्रयोग किया जा सकता है या संभारक पदार्थ या ध्वंस-शील पदार्थ या विषैली या अपायकर गैस या अन्य रसायन या कोई अन्य पदार्थ चाहे जब हो या अन्यथा (या किसी अन्य कारण से आदेश में खतरनाक पदार्थ घोषित किए गए हैं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रवृत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(क) यदि किसी पुलिस अधिकारी को जो हैडक्वार्टर में से नीचे की पंक्ति का नहीं है या इसी नियम के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य लोक सेवक का यह सन्देश होता है कि कोई आयुध, वस्तु जिसका आयुध, गोलाबारूद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या खतरनाक पदार्थ, उप-नियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में, किसी भूमि, यान, वायुयान, जलयान, मकान या किसी अन्य परिसर में या उसके ऊपर हैं तो वह, यदि आवश्यक हो तो बल सहित भूमि, यान वायुयान, जलयान, मकान या परिसर में या जिसके ऊपर उसकी संवेद्य है कि उपनियम (1) के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन बिना या रात में किसी समय किया गया है, प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और उसमें या वहाँ पाया गया आयुध, वस्तु, जिसका आयुध, गोलाबारूद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, या खतरनाक पदार्थ को अभिवृद्ध कर सकेगा जिसके बारे में उसे सन्देश है कि वह ऐसे आदेश के उल्लंघन में वहाँ या उस पर है।

(ख) यदि किसी पुलिस अधिकारी या इस नियम के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य लोक सेवक को यह सन्देश है कि कोई व्यक्ति ऐसा आयुध, वस्तु जिसका आयुध, गोलाबारूद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, या खतरनाक पदार्थ उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में ले जा रहे हैं या उसके कब्जे में है तो ऐसा अधिकारी या अन्य लोक सेवक ऐसे व्यक्ति को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा या तलाशी करवा सकेगा और उसके कब्जे में के या उसके द्वारा ले जाए जा रहे किसी आयुध, वस्तु को जिसका आयुध गोलाबारूद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, या खतरनाक पदार्थों को अभिवृद्ध कर सकेगा जिसके बारे में ऐसे अधिकारी या अन्य लोक सेवक को यह सन्देश है कि वह ऐसे आदेश के उल्लंघन में उसके कब्जे में है या ले जाए गए हैं।

परन्तु इस नियम के उपबन्धों के अनुसरण में किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ही ले जाएगी, अन्यथा नहीं।

(3) इस नियम के उपबन्धों के अधीन अभिवृद्ध कोई आयुध, गोलाबारूद, खतरनाक पदार्थ या अन्य वस्तु सशक्त प्राधिकारी द्वारा आबिष्ट रूप से नष्ट की जा सकेगी या अन्यथा उसका निपटारा किया जा सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन किया गया कोई उल्लंघन निम्न प्रकार दण्डनीय होगा,

(क) यदि किसी ऐसे क्षेत्र में, जो किसी ऐसे क्षेत्र का संपूर्ण या उसका कोई भाग है, जिसे किसी तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन "उपद्रवग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया गया है, कोई उल्लंघन हुआ है तो कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

(ख) ऐसे मामलों में जहाँ किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसका संघर्ष या कोई भाग आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 24क या 24ख के अधीन जारी की गई अधिवृत्तियों के अन्तर्गत आता है, कोई उल्लंघन हुआ है तो कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

(ग) जहाँ किसी ऐसे क्षेत्र में, जो खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) के अन्तर्गत नहीं आता है, कोई उल्लंघन हुआ है वहाँ ऐसा उल्लंघन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

23. आतंकवादियों या विध्वंसकारियों की सहायता : (1) कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में निम्नलिखित क्रियाकलापों में संलग्न नहीं होगा जिससे किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी क्रियाकलाप का किया जाना मुकुर होता है या बनने की संभावना है या जिससे किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी के विपक्ष संक्रियाओं के सफलतापूर्वक संतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

(क) किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी आतंकवादी कार्य या विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का प्रयत्न करने या प्रयत्न करने में संलग्न है या जो उसका पक्ष समर्थन करता है, वृद्धरण करता है, सलाह देता है या उद्बोधन करता है या जानबूझकर मुकुर बनाता है, या कांक्षित नहीं देगा या उनके साथ कोई संविदा नहीं करेगा या

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को या उसके फायदे के लिए किसी धनराशि का संदाय नहीं करेगा; या

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी ऋण या किसी अन्य धनराशि के संदाय के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं देगा; या

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति की ओर से धन निकालने, स्वीकार करने, संदाय करने स्वीकृति या संदाय के लिए प्रस्तुत करने, परकाशण करने, या अन्यथा किसी प्रक्राम्य लिखित के साथ संव्यवहार करने के लिए उसकी ओर से कार्य नहीं करेगा या

(ङ) ऐसे किसी प्रक्राम्य लिखित को स्वीकार, उसका संदाय या अन्यथा उसके साथ व्यवहार नहीं करेगा जो किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी द्वारा या उसकी ओर से या खण्ड (क) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से धारित है, या

(च) किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी के साथ या उसके फायदे के लिए या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट है, कोई अन्य वित्तीय वाध्यता या संविदा नहीं करेगा।

(2) भारत का कोई भी नागरिक जो तत्समय भारत के बाहर है या सरकार की सेवा में के व्यक्ति, जहाँ कहीं भी वे हों या भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान का स्वामी या किसी वायुयान का चालक, आतंकवादियों या विध्वंसकारियों को या उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार को कोई सहायता नहीं देगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, साधारणतया या किसी विशेष क्षेत्र के लिए उपनियम (1) के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे एक या अधिक प्राधिकारियों को, जो वह ठीक समझे, सशक्त कर सकेगी और ऐसे प्राधिकारी, किसी आतंकवादी या विध्वंसकारी या किसी भी शक्ति में किसी आतंकवादी या किसी विध्वंसकारी से संबंध किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा या उसकी ओर से किए गए संव्यवहारों के प्रति निर्देश से संस्थाओं को, जिनके अन्तर्गत बैंक भी हैं, लिखित रूप में ऐसे आदेश या निर्देश जारी कर सकेंगे जो वह ठीक समझे।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो जानबूझकर ऐसे किसी क्रियाकलाप को, जो अधिनियम के अधीन अपराध है, अदम्य करने में या उसके समर्थन में कोई धन उद्यम करता है, या उसका प्रदाय करता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

24. विधिपूर्ण प्राधिकारियों को बाधा पहुंचाना : यदि कोई व्यक्ति स्वच्छता —

(क) संघ के सशस्त्र बलों या किसी राज्य के किसी भी नाम से ज्ञात पुलिस बल के किसी सदस्य को अब यह इस प्रकार अपने कर्तव्य के अनुक्रम में कार्य कर रहा है ; या

(ग) किसी प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को जो इन नियमों के द्वारा या उनके अनुसरण में उसे प्रवृत्त या उस पर अधिरोपित किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर रहा है या अगथा आतंकवादी कार्यों और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निवृत्ति के लिए संक्रियाओं के संबंध में किन्हीं विधिपूर्ण कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, या

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को जो यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या किसी व्यक्ति के आदेश का पालन कर रहा है या जो अगथा इन नियमों के अनुसरण में अपने कर्तव्य के अनुसरण में कार्य कर रहा है, बाधा पहुंचावेगा या उसका प्रतिरोध करेगा, या उसके साथ अगथा अशुभ पहुंचाएगा या हस्तक्षेप करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से अथवा दोनों से, वण्डीय होगा।

25. नियमों का उल्लंघन करने का प्रयत्न आदि : कोई व्यक्ति, जो इन नियमों या उनके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, बुद्धिरित करेगा या उल्लंघन की तैयारी के लिए किसी कार्य को बुद्धिरित करने का प्रयत्न करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति, उस उपबन्ध का या उस आदेश का उल्लंघन किया है।

26. कम्पनियों द्वारा अपराध : (1) जहाँ इन नियमों या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबन्धों के विषय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस कम्पनी के कारखाने के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरवायी या और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध का बोझ समझा जाएगा और तबनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और वण्डित किए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपनियम की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी वण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या उसने ऐसे अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई ऐसा अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की समझ या सीमानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का बोझ समझा जाएगा और तबनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और वण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है, और

(ख) "निदेशक" से,—

(i) किसी फर्म के संबंध में उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

(ii) किसी सोसायटी या व्यक्तियों के अन्य संगम के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे सोसायटी या अन्य संगम के नियम के अधीन यथास्थिति, सोसायटी या अन्य संगम के कार्यकाल का प्रबन्ध सौंपा गया है।

27. कुछ मामलों में सबूत का भार : जहाँ किसी व्यक्ति को, इन नियमों में से किसी के या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए अभियोजित किया जाता है, जो उसे विधिपूर्वक प्राधिकार या प्रतिहेतु या किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र या अनुज्ञा के बिना ऐसा कोई कार्य करने से या किसी चीज का कब्जा रखने से प्रतिषिद्ध करता है, तो यह साबित करने का भार उस पर होगा कि उसके पास ऐसा प्राधिकार या प्रतिहेतु यथास्थिति ऐसा अपेक्षित अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र या अनुज्ञा थी।

28. तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति : (1) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, किसी महानगर क्षेत्र में पुलिस आयुक्त या किसी जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विधि के अधीन समझ किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों का कोई उल्लंघन या आतंकवादी कार्यों या विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निवृत्ति के लिए संक्रियाओं पर प्रतिफल प्रभाव डालने वाला कोई अपराध किसी स्थान में हुआ है, हो रहा है या होने वाला है तो वह वारंट द्वारा किसी कार्टेजुल से ऊपर के रैंक के किसी पुलिस अधिकारी को :

(क) वारंट में विनिर्दिष्ट रीति में उस स्थान पर प्रवेश और उसकी तलाशी लेने के लिए ; और

(ख) ऐसे किसी स्थान में या उस पर पाई गई किसी चीज को जिसके लिए पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह पूर्वोक्त क्षेत्र में ऐसे किसी उल्लंघन या अपराध के प्रयोजन के लिए या गैरे संबंध में प्रयोग की गई है, की जा रही है या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है, अभिप्रेत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और

वण्ड प्रक्रिया या संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहाँ तक वे लागू हों, ऐसी तलाशी या अभिग्रहण को दैसे ही लागू होंगे जैसे वे संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए किसी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

(2) ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष उपनियम (1) के अधीन अभिग्रहीत कोई चीज प्रस्तुत की जाती है, ऐसे अभिग्रहण के तथ्य की रिपोर्ट तुरंत राज्य सरकार को देगा और उसके आदेशों से प्राप्त होते तक इस प्रकार अभिग्रहीत किसी चीज को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकेगा या उसकी निरापेक्ष अभिरक्षा के लिए ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) उपनियम (1) के अधीन अभिग्रहीत किसी भी चीज का अध्ययन ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार निरुद्ध करे।

(4) इस नियम में, और नियम 57 में, "स्थान" के अन्तर्गत कोई घर, भवन, तम्बू, यान और वायुयान है।

29. तलाशी लेने की शक्तियाँ : (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगी —

(क) अन्तर्देशीय जल मार्गों पर पाए गए किसी जलयान का या किसी यान या वस्तु का रोकना और उसकी तलाशी ;

(ख) किसी ऐसे स्थान (जिसके अन्तर्गत कोई जलयान भी है, चाहे वह कहीं भी रखा जाता है) की तलाशी और इस उपनियम के अधीन तलाशी लिए जाने पर पाई गई किसी चीज का (जिसके अन्तर्गत कोई जलयान, यान या वस्तु भी है) अभिग्रहण जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह अभिनिधायक या इन नियमों के अधीन वण्डीय कोई अपराध किए जाने के लिए प्रयोग की गई है, प्रयोग की जा रही है या जिसका प्रयोग किया जाने वाला है।



(2) उपनियम (1) के अधीन सशस्त्र कोई भी व्यक्ति, अपने द्वारा किए गए किसी अभिग्रहण की एक व्यवस्था रिवॉल्वर सुरत राज्य सरकार द्वारा और उसके आदेश के प्राप्त होने तक इस प्रकार अभिग्रहीत किसी वस्तु को अतिरिक्त में निष्काश कर सकेगा या उसको निरापव अभिरक्षा के लिए ऐसे अन्य कदम उठा सकेगा, जो वह उचित समझे।

(3) उपनियम (1) के अधीन सशस्त्र किसी व्यक्ति द्वारा अभिग्रहीत किसी वस्तु का व्यवस्था ऐसी रीति में किया जाएगा जो अभिग्रहीत व्यावसायिक निष्पत्ति करें।

(4) उपनियम (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र कोई व्यक्ति, किसी ऐसे सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग की भावना जिसके बारे में सरकार ने उसे सशस्त्र किया है वही शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।

30. भूमि पर प्रवेश और उसका निरीक्षण संघ के सशस्त्र बलों का या राज्य पुलिस बल का कोई भी सदस्य जो इस प्रकार अपने कर्तव्य के अनुक्रम में कार्य कर रहा है, और इस नियम के अधीन कार्य करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति—

(क) अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों में से किसी के द्वारा उस भूमि के संबंध में प्रवृत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा ;

(ख) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या उस भूमि के संबंध में उन शक्तियों में से किसी का प्रयोग किया जाना है, और, यदि ऐसा है तो किस रीति में किसी भूमि में प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकेगा ;

(ग) आतंकवादी कार्यों और विध्वंसकारी क्रियाकलापों के निवारण और उनसे निपटने के लिए संकियाओं से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए (यन्त्रों या यान के साथ या उसके बिना) किसी भूमि से गुजर सकेगा।

31. नियमों, आदेशों आदि को कार्यान्वित करने के लिए शक्तियां :

(1) ऐसा कोई प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति, जो कोई आदेश करने या किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिनियम या नियमों में से किसी द्वारा या उसके अनुमरण में सशस्त्र किया गया है, इन नियमों द्वारा या उनके अधीन विहित किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगा या करवा सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा, जिसके अन्तर्गत किसी परिसर को ताला लगाया या उसको सील करना भी है जब तक कि उसको सलासी या निरीक्षण या उसमें किसी वस्तु या चीज का अभिग्रहण पूरा नहीं होता है, जो ऐसे किसी प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति की राय में, ऐसे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए या किसी उत्प्रेषण को रोकने या उसकी परिशुद्धि के लिए या ऐसी शक्ति के प्रभावी प्रयोग के लिए आवश्यक हो।

(2) जहाँ इन नियमों के उपबन्धों के संबंध में उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र कोई प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति नहीं है, वहाँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या करवा सकेगी और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगी या करवा सकेगी जो उस सरकार की राय में ऐसे उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने या उसके किसी संग को रोकने या उसके परिशोधन के लिए आवश्यक हो।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कार्रवाई करने की शक्तियों के अन्तर्गत किसी भी भूमि या अन्य सम्पत्ति पर प्रवेश करने की शक्ति भी है।

[फा.सं. 6/4/85-विधिक सेल]

टी. टी. बैजानिन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th November, 1986

G.S.R. 1200(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) “Act” means the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985 (31 of 1985);

(b) “empowered authority” means any authority being the Central Government or a State Government or the Administrator of a Union territory under article 239 of the Constitution or an officer of the Central Government not lower in rank than that of a Joint Secretary to that Government or an officer of a State Government or a Union territory Administration not lower in rank than that of a District Magistrate or an officer competent to exercise under any law the powers of a District Magistrate.

(c) “essential service” shall include those services which the Central Government have declared to be such under the provisions of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981);

(d) “essential supplies” means articles which the Central Government being of opinion that the maintenance of supply thereof is essential to the life of the community, declares by an order in writing to be an essential article;

(e) “media” shall include, besides newspapers and other printed material normally circulated, hand-written posters, booklets, hand-bills or display of slogans at public places;

(f) “notified” and “notification” means notified and notification in the Official Gazette;

(g) “official document” includes any passport, pass, permit certificates, licence, notice or other document issued by or under the authority of Government or any officer of the Armed Forces of the Union or any police officer;

(h) “prescribed” means prescribed by any order or direction made or given in pursuance of any of these Rules;

(i) “prohibited place” means a prohibited place as defined in clause 8 of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923);

- (j) "protected area" means any area so declared under rule 8;
- (k) "protected place" means a place so declared by the Central Government or a State Government and includes any court room or building where trials, or other proceedings in connection with cases under the Act, are held;
- (l) "public servant" includes any public servant as defined in the Indian Penal Code (45 of 1860);
- (m) "speech" shall include pre-recorded speeches;
- (n) "wireless telegraphy apparatus" has the same meaning as in the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933).

3. Interpretation.—The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply to the interpretation of these rules as it applies to the interpretation of a Central Act.

(2) Any reference in these rules to a Central Act shall, in relation to any area wherein that Central Act is not in force, be construed as including a reference to the corresponding law in force in that area.

(3) If any question arises as to the interpretation of the rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

4. Previous approval of the Central Government required in certain cases:—

Notwithstanding anything contained in these rules, no power conferred or duty imposed upon the State Government or the Administrator of a Union Territory by such of the provisions of these rules as may be specified by the Central Government by notified order shall, with effect from such date as may be specified in such order, be exercised or discharged by any State Government or the Administrator of a Union territory, as the case may be, as specified in the order or by any officer or authority authorised in that behalf by that State Government or Administrator, except with the previous approval of the Central Government.

5. Non-compliance with these Rules or orders made thereunder:—

If any person to whom any provision of these rules relates, or to whom any order made in pursuance of these rules is addressed or relates, or who is in occupation, possession or control of any property, moveable or immovable, or other thing to which such provision relates, or in respect of which such order is made.

- (a) fails without lawful authority or excuse—
  - (i) in relation to such provision as relates to himself, or
  - (ii) in respect of any property, moveable or immovable or other thing of which he is in occupation, possession or control,

to comply or to secure compliance, with such provision or order; or

(b) evades, or attempts to evade, by any means such provision or order—he shall be deemed to have contravened such provision or order; and in these rules the expression "contravention" with its grammatical variations includes any failure, evasion or attempt to evade.

6. Prohibited places.—(1) No person shall, without the permission of the Central Government or the State Government enter or be on or in or pass over or loiter in the vicinity of, any prohibited place.

(2) Where in pursuance of sub-rule (1) any person is granted permission to enter, or to be on or in, or to pass over, a prohibited place, that person shall, while acting under such permission, comply with such orders for regulating his conduct as may be given by the Central Government or the State Government.

(3) Any police officer or any other person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government may search any person entering, or seeking to enter, or being on or in, or leaving or passing over or seeking to pass over, a prohibited place and any vehicle, vessel, aircraft or article brought in by such person, and may, for the purpose of the search, detain such person, vehicle, vessel, aircraft or article:

Provided that no female shall be searched in pursuance of this sub-rule except by a female.

(4) If any person is in a prohibited place in contravention of this rule, then, without prejudice to any other proceedings which may be taken, against him, he may be removed therefrom by any police officer or by any other person authorised in this behalf by the Central Government or the State Government.

(5) If any person is in a prohibited place in contravention of any of the provisions of this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to three years and shall also be liable to fine.

7. Protected places.—(1) If, as respects any place or class or places, the Central Government, or the State Government considers it necessary or expedient for the prevention of and for coping with terrorist and disruptive activities that special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorised persons or to exclude any person or class of persons, from having access to or being present in or in the vicinity of such a place or places, that Government may by order declare that place, or as the case may be, every place of that class to be a protected place, for such period as may be specified in the order. On and after such day, as may be specified in, an subject to any exemptions as may be made in, such order, no person not being a public servant, or a Judge, or an officer of the court, or an accused, as the case may be, shall be therein except in accordance with the terms of a permit in writing granted to him by an authority or person specified in the said order.

(2) A copy of the order issued under sub-rule (1) shall be affixed in English and in vernacular of the locality at some conspicuous part of the protected place.

(3) Any police officer, or any other person authorised in this behalf by the empowered authority may search any person entering or seeking to enter, or being in or in, or leaving a protected place, and any vehicle or article brought in by such person, and may, for the purpose of the search detain such person, vehicle or article:

Provided that no female shall be searched in pursuance of this sub-rule except by a female.

(4) If any person is in or passes over, a protected place in contravention of this rule, or refuses to submit himself or the vehicle or article for the time being in his possession for search, then, without prejudice to any other proceedings which may be initiated against him, he may be removed therefrom by or under the direction of any police officer or other person on security duty in such a place. Thereupon the vehicle or article found to be in possession of the person so removed may also be seized or directed to be seized.

(5) Any contravention of the provisions of this rule shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but which may extend upto three years and shall also be liable to fine.

#### 8. Protected areas.—

(1) If the Central Government or the States Government consider it necessary or expedient, for the prevention of and for coping with terrorist and disruptive activities, to regulate the entry of persons into any area, that Government may, without prejudice to the provisions of any other rule, by order, declare the area to be protected area, and thereupon, or so long as the order is in force, such area shall be a protected area for the purposes of these rules.

(2) A copy of the order issued under sub-rule (1) shall be affixed in English and in vernacular of the locality at some conspicuous part of the protected area.

(3) On and after such date as may be specified in, and subject to any exemption for which provision may be made by an order made under sub-rule (1), no person who was not at the beginning of the said day residing in the area declared to be a protected area by the said order shall be therein except in accordance with the terms of a permit granted to him by an authority or person specified in the said order.

(4) Any police officer, or any other person authorised in this behalf by the Central Government, or the State Government may search any person entering or seeking to enter or being on or in or leaving a protected area, and any vehicle, vessel, aircraft or article brought in by such person, and may, for the purposes of search, detain such person, vehicle, vessel, aircraft or article :

Provided that no female shall be searched in pursuance of this sub-rule except by a female.

(5) If any person is in, or passes over, a protected area, in contravention of the provision of this rule, then, without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, he may be removed therefrom by or under the direction of any police officer or any member of the Armed Forces of the Union on duty in the protected area.

(6) If any person is in a protected area in contravention of any of the provisions of this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend upto three years and shall also be liable to fine.

9. Forcing or evading a guard.—Any person, whether alone or as part of a group of persons, who effects or attempts to effect entry into, or passes over, or attempts to pass over a prohibited place or a protected place—

- (a) by using or threatening to use criminal force to any person posted for the purpose of protecting or controlling access to such place, or
- (b) after taking precautions to conceal his entry or attempted entry from any such person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

10. Orders for certain places and areas.—(1) without prejudice to the provisions of any other rule, the Central Government or State Government as respects any other place or area in relation to which it appears to it to be necessary or expedient to take special precautions for prevention of, and for coping with, terrorist activities, may, make orders for controlling or regulating the admission of persons to, and the conduct of persons in, and in the vicinity of, such place or area.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, orders made under sub-rule (1) in relation to any place or area may, make provision—

- (a) for restricting the admission of persons or class of persons to such place or area and for removing therefrom any person who is therein in contravention of the orders or who has been convicted of—
  - (i) any contravention of the provisions of these rules or ;
  - (ii) any offence against public order;
- (b) for requiring the presence of any person, or class of persons, in such place or area (to be notified by the empowered authority) and for requiring any person who has been convicted of any such offence as is mentioned in clause (a) of this sub-rule to report his movements while in such place or area and to observe any other condition imposed upon him by such authority.
- (c) for prohibiting any person or class of persons in such place or area from being in possession or control of any prescribed article.



(3) Any order made under this rule in respect of a place, which is not a prohibited place or a protected place, may direct that all or any of the provisions of these rules which are expressed to apply to, or in relation to, a prohibited place or protected place, shall apply to or in relation to the place in respect of which the order is made either without modification or subject to such modifications as may be specified in the order.

(4) If any person contravenes any order made under this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months and may extend upto three years and shall also be liable to fine.

11. Trespassing on certain premises.—(1) No person shall commit criminal trespass on, or in any premises in the vicinity of, any premises used or appropriated for any of the purposes of the Government or for coping with terrorist acts or disruptive activities, or for protection from terrorists and disruptionists.

(2) If any person is found trespassing on any premises in contravention of sub-rule (1) he may, without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, be removed from such premises by any police officer or any other person acting on behalf of Government, or by the person occupying the premises, or by any person authorised by him.

(3) No person shall, for any purpose prejudicial to the public safety, or for endangering the safety of any public servant or of any person bound by oath under the Constitution to uphold the sovereignty and territorial integrity of India be in, or in the vicinity of any such premises are referred to in sub-rule (1); and where, in any proceedings taken against a person by virtue of this sub-rule it is proved that at the material time he was present, in, or in the vicinity of the premises, he prosecution may thereupon adduce such evidence of the character of such person (including evidence of his having been previously convicted of any offence) as tends to show that he was so present for a purpose prejudicial to the public safety or to the safety of any public servant or any person bound by oath under the Constitution to uphold the sovereignty and territorial integrity of India.

(4) If any person contravenes any of the provisions of this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend in the case of contravention of sub-rule (3), to seven years and in any other case to three years and shall also be liable to fine.

12. Loitering near certain premises.—(1) No person loitering in the vicinity of any protected place or a prohibited place or any other place as is referred to in sub-rule (1) of rule 10 shall continue to loiter in that vicinity after being ordered to leave it by any police officer or any other person acting on behalf of Government or by the person in occupation of the said premises, or any person authorised by him.

(2) If any person contravenes the provisions of sub-rule (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

13. Power to close roads, etc.—(1) The Central Government or the State Government may, for reasons to be recorded in writing, by order, prohibit or restrict for such period as may be specified in the order,—

- (a) the use of any road, pathway, canal or water way;
- (b) the passage of any person, animal or vehicle over any land or the carriage of the number of persons by any such animal or vehicle.
- (c) the travelling of any person or class of persons from travelling by any vehicle or class of vehicles or by any road, pathway, canal or waterway.

(2) If any person contravenes any order made under sub-rule (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may not be less than six months but may extend to seven years and shall also be liable to fine.

14. Control of Telephones and Telegraphs.—(1) where the empowered authority is satisfied or has reasonable grounds to suspect that a telephone connection of a subscriber or the telephone apparatus, is being used for purposes of, or for aiding or abetting or for making any preparation to aid or abet any terrorist or disruptive activity, may by order.—

- (a) direct that the telephone connection in question be cut off for such period as may be specified; and that all telephone apparatus and fittings on the premises be taken possession of by such person as may be specified in that order;
- (b) authorise any person, empowered by him in this behalf, by order in writing to listen in to all conversations or any specified conversation over any telephone system;
- (c) make provision for suspending or regulating the use otherwise than for government purposes, of any telegraph or telephone service in any area, which for the time being may constitute, or form part of any area that had been declared to be a disturbed area under any enactment for the time being in force;
- (d) assume the control or direction, or direct any person to assume the control or direction, of any private telephone exchange or any connection with any such exchange.

(2) If any person contravenes any order made under the provisions of sub-rule (1) he shall be punishable with imprisonment for a term which may not be less than six months but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

15. Power to prohibit and to search, etc. travellers conveying non-postal correspondence.—(1) In this rule "photograph" includes any photographic plate, photographic film or other sensitised article which has been exposed in a camera whether such plate, film or other article has been developed or not.



(2) The Central Government may, by order, make provision for securing that, subject to any exemptions for which provision may be made by the order, and except in accordance with such conditions as may be contained therein, no article whatsoever recording information and no document, pictorial representation photograph or gramophone record or cassette which advocates, abets, advises or incites or knowingly facilitates the commission of a terrorist activity or disruptive activity, shall be sent or conveyed, otherwise than by post, into or from India.

(3) No person shall have any article in his possession for the purpose of sending or conveying it in contravention of an order made under sub-rule (2).

(4) Any prohibition or restriction imposed by an order under sub-rule (2) on the sending into, or conveying from India of articles, shall be deemed to have been imposed under section 11 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and all the provisions of that Act for the purpose of detection, search and seizure shall have effect accordingly:

Provided that notwithstanding anything contained in the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any orders made thereunder, a complaint regarding contravention of this rule shall be triable by a Designated Court within whose jurisdiction such a contravention took place or such other Designated Court to which the case may be transferred by the Central Government in terms of sub-section (2) or sub-section (3) of section 9 of the Act, and the accused person shall, upon conviction, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

(5) Any officer of Customs may, for the purpose of carrying into effect the provisions of this rule, take such steps (including the subjection of the article to any process) as may be necessary for ascertaining whether an article does or does not record any information of the nature specified.

(6) The Central Government or the State Government may, by order, authorise any person for the purposes of this rule to exercise the powers, and perform the duties conferred or imposed on a Collector of Customs or any subordinate officer of customs by or under the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

16. Entering India.—(1) The Central Government may, by notified order, make provision for securing that, subject to such exemptions as may be provided for in the order, any person or class of persons shall not, on coming from a place outside India, enter India elsewhere than at such place as may be specified in the order.

(2) If any person enters India in contravention of any order made under sub-rule (1) or of the provisions of, or any rule or order made under the Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920), he shall, without prejudice to any other proceedings which may be taken against him, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months, but may extend to five years and shall be liable to fine.

17. Information to be supplied by persons entering India:—

(1) The Central Government may, by notified order, require any person or class of persons who has entered India and about whom there is prima facie ground to believe that such person or class of persons is likely to indulge in any activity, while in India that may disrupt harmony amongst different sections of the people in India or otherwise incite, advocate, abet or advise or knowingly facilitate any terrorist or disruptive activity in India, since such date as may be specified, to furnish to the empowered authority in such manner as may be specified such particulars regarding himself his dependent, his past and prospective movements and any travel document in his possession, as may be specified in that order.

(2) If any person contravenes any order made under sub-rule (1) he shall be punishable with imprisonment which may not be less than six months, or with fine which may extend to one thousand rupees.

18. Communication with persons assisting terrorists and disruptionists.—(1) No person shall communicate or associate with any person or class of persons if he has reasonable cause to believe that such other person or class of persons is engaged in assisting the terrorists and disruptionists.

(2) If any person contravenes any of the provisions of this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

19. Articles likely to afford information or other assistance to the terrorists and disruptionists.—

(1) In this rule "information likely to assist the terrorists and disruptionists" means any information, whether true or false, or any document or other record whatsoever containing or purporting to contain, or calculated, directly or indirectly, to convey and information whether true or false, that may, or is intended directly or indirectly to, or is likely to cause disaffection, or alarm, or to prejudice maintenance of peaceful conditions in any area or part of India or to promote feelings of ill will, enmity or hatred between different sections of the people of India or otherwise facilitate the commission of any terrorist act or disruptive activity, that is to say—

- (a) any operations or projected operations of any of the Armed Forces of the Union or the Police Force, by whatever name called, of a State;
- (b) the conditions of the citizens of India or of any class thereof or the sympathies of such citizens or class, as regards the sovereignty and territorial integrity of India;
- (c) any arrangements relating to the protection of transport, communications, prohibited places, protected places, supplies and services essential to the community, security of any public servant or persons bound by oath under the Constitution to uphold the sovereignty and integrity of India and

would include any information which is intended or is likely :—

- (i) to bring into hatred or contempt, or to excite disaffection towards the Government established by law in India;
- (ii) to bring into hatred or contempt, or excite disaffection towards the Armed Forces of the Union or the Police Force, by whatever name called, of a State or any public servant or class of public servants;
- (iii) to promote feelings of enmity or hatred or otherwise affect the harmony between different classes of persons in India;
- (iv) to cause fear or alarm to the public or to any section of the public; or
- (v) to instigate directly or indirectly the use of criminal force against public servants generally or any class of public servants or any individual public servant.

(2) No person shall without lawful authority or excuse—

- (a) obtain, collect, record, elicit, make, print or publish, or distribute or communicate or spread by any means whatsoever, to any other person or class of persons any information likely to assist the terrorists and disruptionists; or
- (b) make, print, publish or distribute any publication containing, or communicate to any person by any means whatsoever, any such information;
- (c) help the author, editor, printer and publisher of, or any person who otherwise makes or produces any information likely to assist the terrorists and disruptionists, or any person including a reporter or correspondent of any news agency or journalist distributes or sells any information or report of that nature, knowing it to be of such nature;
- (d) help the proprietor, manager or any other person in control of any place in which, or every person who takes part in any public performance of any play, pantomime, drama or recitation in the course of which any information likely to assist the terrorists and disruptionists is published, or any video or cassette containing such information is exhibited.

(3) If any person contravenes any of the provisions of this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

20. Prohibition of publishing matter derived from terrorists, or disruptionists etc.—(1) No person shall, without lawful authority, make, print, publish or distribute any document containing or spread by any other means whatsoever, any matter derived from terrorists or disruptionists, their sympathisers or associates, or sources sponsored or utilised by or

otherwise connected with terrorists, disruptionists, or their associates or sympathisers.

(2) In any proceedings arising out of a contravention of sub-rule (1) where it appears to the Designated Court that the substance of any matter—

- (i) broadcast from any wireless broadcasting station operated or controlled by the terrorists and disruptionists, or
- (ii) published in any leaflet distributed by the terrorists and disruptionists, by any means whatsoever, is at any subsequent time reproduced, whether in the same or a different form and whether with or without comments, in any document, or cassette the Designated Court may presume that the matter contained in the document or cassette, as the case may be, is derived from a terrorist or disruptionist source.

(3) If any person contravenes the provisions of this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine.

Explanation : In this rule "document" includes gramophone records, cassettes, tapes, sound-tracks and any other articles on which sound has been recorded with a view to their subsequent reproduction.

21. Measures in relation to certain premises.—

(1) The Central Government or the State Government may by order as respects such premises as may be specified in the order—

- (a) require the owner or the occupier of the premises to take such measures as may be specified in the order, or
- (b) authorise any person to take such measures as may be so specified,

which are in the opinion of that Government necessary to prevent the use of the premises by terrorists or disruptionists or for committing or planning or preparing for any terrorist act or disruptive activity, or to minimize danger to persons and property in or in the vicinity of such premises during any operations against terrorists and disruptionists.

(2) If any person contravenes any order made under this rule, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months and shall also be liable to fine.

22. Possession, use or Disposal of arms, explosives, etc.—(1) The Central Government or the State Government may, by general or special order, prohibit, restrict or impose conditions on, the possession, carrying, use, sale or other disposal of—

- (a) arms or articles capable of being used as arms;
- (b) ammunition;
- (c) dangerous substances.

**Explanation :** For the purposes of this rule, "dangerous substances" mean—

- (i) substances, which are or are declared to be explosives within the meaning of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), and
- (ii) substances which [being substances capable of being used in the manufacture of explosives, or being corrosive substances or inflammable substances or poisons or noxious gases or other chemicals or any other substances (whether biological or otherwise) or for any other reason] are declared in the order to be dangerous substances.

(2) Without prejudice to any powers conferred by or under any other law for the time being in force—

- (a) if any police officer not below the rank of head constable or any other public servant authorised by the empowered authority to act under this rule, suspects that any arms, articles capable of being used as arms, ammunition or dangerous substances are in or upon any land, vehicle, aircraft, vessel, building or other premises in contravention of an order made under sub-rule (1), he may enter, if necessary by force, and search the land, vehicle, aircraft, vessel, building or premises in or upon which he suspects that a contravention of an order made under sub-rule (1) has been committed at any time of the day or night and may seize any arms, articles capable of being used as arms, ammunition, or dangerous substances found therein or thereon which he suspects to be therein or thereon in contravention of such order.
- (b) if any police officer, or any other public servant authorised by the empowered authority to act under this rule, suspects that any person is carrying, or is in possession of arms, articles capable of being used as arms, ammunition, or dangerous substances in contravention of an order made under sub-rule (1), such officer or other public servant may stop and search or cause to be searched such person and seize any arms, articles capable of being used as arms, ammunition, or dangerous substances possessed or carried by him which such officer or other public servant suspects to be possessed or carried in contravention of such order :

Provided that no female shall be searched in pursuance of the provisions of this rule except by a female.

(3) Any arms, ammunition, dangerous substances or other articles seized under the provisions of this rule may be destroyed or otherwise disposed of as may be ordered by the empowered authority.

(4) Any contravention of any order made under this rule shall be punishable as follows :—

- (a) if the contravention had taken place in an area which forms the whole or any part in an area which has been declared to be 'disturbed area' under any enactment for the time being in force, with imprisonment which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.
- (b) in cases where the contravention had taken place in an area the whole or part of which is covered by notifications issued under section 24A or 24B of the Arms Act, 1959 (54 of 1959) shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.
- (c) where the contravention has taken place in an area not covered by clause (a) or (b), such contravention shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and shall also be liable to fine.

23. Assistance to terrorists or disruptionists.—

(1) No person shall directly or indirectly indulge in any of the following activities, which are or are likely to facilitate the commission of a terrorist act or disruptive activity or which are likely to prejudice the successful conduct of operations against any terrorist or disruptionist,—

- (a) advance money to, or enter into any contract with any terrorist or disruptionist or any person engaged in conspiring or attempting to commit or who advocates, abets, advises or incites or knowingly facilitates the commission of a terrorist act or a disruptive activity, or any act preparatory to such a terrorist or disruptive activity; or
- (b) pay any sum of money to or for the benefit of any such person; or
- (c) give any security for the payment of any debt or any other sum of money for the benefit of such a person; or
- (d) act on behalf of such a person in drawing, accepting, having, presenting for acceptance or payment, negotiating, or otherwise dealing with any negotiable instrument; or
- (e) accept, have or otherwise deal with any negotiable instrument which is held by or on behalf of a terrorist or a disruptionist or such other person as specified in clause (a); or
- (f) enter into any other financial obligation or contract with or for the benefit of any terrorist or disruptionist or any such person as specified in clause (a).



(2) No citizen of India who is for the time being outside India or persons in the service of the Government, wherever they may be, or the master of any vessel or the pilot of any aircraft registered in India shall extend any assistance whatsoever to terrorists or disruptionists or such other persons as specified in sub-rule (1).

(3) The Central Government, may, either generally or for any particular area, empower one or more authorities as it may deem fit for securing compliance with the provisions of sub-rule (1) and such authorities may issue such orders or directions to institutions including banks, in writing, as it may deem fit, with reference to transactions made by or on behalf of any terrorist or disruptionist or any other person connected with a terrorist or a disruptionist in any manner whatsoever.

(4) Any person who knowingly expends or supplies any money in furtherance or support of any activity which is an offence under the Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.

24. Obstructing lawful authorities.—If any person voluntarily obstructs, or offers any resistance to, or impedes or otherwise interferes with—

- (a) any member of the Armed Forces of the Union or the Police Force by whatever name called of a State acting in the course of his duty as such, or
- (b) any authority, officer or person exercising any powers, or performing any duties, conferred or imposed upon it or him by or in pursuance of these, rules, or otherwise discharging any lawful functions in connection with the operations to prevent and cope with the terrorist acts and disruptive activities, or
- (c) any person who is carrying out the orders of any such authority, officer or person as aforesaid or who is otherwise acting in accordance with his duty in pursuance of these rules, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

25. Attempts, etc. to contravene the rules.—Any person who attempts to contravene, or abets, or attempts to abet, or does any act preparatory to, a contravention of, any of the provisions of these rules or of any order made thereunder, shall be deemed to have contravened that provision or, as the case may be, that order.

26. Offences by companies.—(1) Where an offence against the provisions of these rules, or of any order made thereunder, has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-rule shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where any such offence has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of, any director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation : For the purposes of the rule,—

- (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "director",—
  - (i) in relation to a firm, means a partner in the firm,
  - (ii) in relation to a society or other association of individuals, means the person who is entrusted, under the rules of the society or other association, with the management of the affairs of the society or other association, as the case may be.

27. Burden of proof in certain cases.—Where any person is prosecuted for contravening any of these rules or order made thereunder which prohibits him from doing an act or being in possession of a thing without lawful authority or excuse or without a permit, licence, certificate or permission, the burden of proving that he had such authority or excuse or, as the case may be, the requisite permit, licence, certificate or permission, shall be on him.

28. Power to issue search warrants.—(1) If a District Magistrate, Commissioner of Police in a Metropolitan area or any officer competent to exercise under any law the powers of a District Magistrate has reason to believe that a contravention of any of these rules or any offence prejudicial to the operations to prevent and cope with the terrorist acts and disruptive activities has been, is being, or is about to be, committed in any place, he may be warrant authorise any police officer above the rank of a constable—

- (a) To enter and search the place in the manner specified in the warrant; and
- (b) to seize anything found in or on such place which the police officer has reason to believe has been, is being, or is intended to be, used, for the purpose of or in connection with any such contravention or offence as aforesaid, and

the provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, so far as they may be applicable, apply to any such search or seizure as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the Code.



(2) Any Magistrate before whom anything seized under sub-rule (1) is conveyed shall forthwith report the fact of such seizure to the State Government and, pending the receipt of its orders may detain in custody anything so seized or make such other order for its safe custody as he may think proper.

(3) Anything seized under sub-rule (1) shall be disposed of in such manner as the State Government may direct.

(4) In this rule, and in rule 57 "place" includes a house, building, tent, vehicle and aircraft.

29. Powers of search.—(1) The Central Government or the State Government may by general or special order empower any person to—

- (a) stop and search any vessel found in inland waterways or any vehicle or animal;
- (b) search any place (including any vessel wherever found) and seize anything found on search under this sub-rule (including a vessel vehicle or animal) which he has reason to believe has been, is being, or is about to be, used for the commission of any offence punishable under the Act or these rules.

(2) Any person empowered under sub-rule (1) shall forthwith report to the State Government in detail any seizure made by him and, pending the receipt of its orders may detain in custody anything so seized or take such other steps for its safe custody as he may think proper.

(3) Anything seized by a person empowered under sub-rule (1) shall be disposed of in such manner as the Designated Court may direct.

(4) A person empowered by the Central Government or the State Government under sub-rule (1) may authorise any other person to exercise like powers as his own in the whole or any part of the area in respect of which the Government has empowered him.

30. Entry and inspection of land.—Any member of the Armed Forces of the Union or of the State Police Force acting in the course of his duty as such, and any person authorised by the Central Government or the State Government to act under this rule :—

- (a) may enter on any land for the purpose of exercising any of the powers conferred in relation to that land by any of the provisions of the Act and these rules;
- (b) may enter and inspect any land for the purpose of determining whether, and, if so, in what manner, any of those powers are to be exercised in relation to that land;
- (c) may, for any purpose connected with the operations to prevent and cope with terrorist acts and disruptive activities, pass (with or without animals or vehicles) over any land.

31. Powers to give effect to Rules, orders, etc.—

(1) Any authority, officer or person who is empowered by or in pursuance of the Act or any of these rules to make any order, or to exercise any other power may, in addition to any other action prescribed by or under these rules, take, or cause to be taken, such steps and use, or cause to be used, such force, including the locking or sealing of any premises until a search or inspection thereof or seizure of any articles or things therein has been completed, as may in the opinion of such authority, officer or person, be reasonably necessary for securing compliance with, or for preventing or rectifying any contravention of, such order, or for the effective exercise of such power.

(2) Where in respect of any of the provisions of these rules there is no authority, officer or person empowered to take action under sub-rule (1), the Central Government or the State Government may take, or cause to be taken, such steps and use, or cause to be used, such force as may in the opinion of that Government be reasonably necessary for securing compliance with or preventing or rectifying any breach of such provision.

(3) For the avoidance of doubt, it is hereby declared that the power to take steps under sub-rule (1) or under sub-rule (2) includes the power to enter upon any land or other property whatsoever.

[F. No. 6/4/85-Legal Cell]

C. T. BENJAMIN, Jt. Secy.

